Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

* Vol-3* *Issue-2* *February 2026*

www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका: QUAD और चीन एक चुनौती

विजय कुमार यादव

शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा।

Article Info: *(Recieved- 09/12/2025, Accept- 18/01/2026, Published- 03/02/2026)*

DOI- 10.70650/rvimj.2026v3i2006

सारांश

21वीं सदी में इंडो–पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक राजनीति, व्यापार, ऊर्जा और सामरिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव, सैन्य विस्तार और आक्रामक विदेश नीति ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। इसके परिणामस्वरूप भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच विकसित Quad एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मंच के रूप में उभरा है। भारत इंडो–पैसिफिक में "मुक्त, समावेशी और नियम–आधारित व्यवस्था" का समर्थक रहा है। यह शोध लेख इंडो–पैसिफिक की अवधारणा, भारत की रणनीतिक भूमिका, Quad की उपयोगिता तथा चीन की चुनौती का विश्लेषण करता है। अध्ययन में यथार्थवादी (Realist) दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि भारत अपनी समुद्री सुरक्षा, आर्थिक हितों, क्षेत्रीय नेतृत्व और चीन की विस्तारवादी नीतियों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। लेख में यह भी विश्लेषित किया गया है कि भविष्य में इंडो–पैसिफिक भारत की विदेश नीति का केंद्रीय आयाम बन सकता है।

मुख्य शब्द– इंडो–पैसिफिक, Quad, चीन, भारत की विदेश नीति, समुद्री सुरक्षा, भू–राजनीति।

परिचय

वैश्विक राजनीति में शक्ति–संतुलन का केंद्र धीरे–धीरे अटलांटिक क्षेत्र से एशिया–प्रशांत की ओर स्थानांतरित हो रहा है। इसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप "इंडो–पैसिफिक" की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है। इंडो–पैसिफिक केवल एक भौगोलिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया केंद्र है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार का प्रमुख मार्ग है, जहाँ विश्व के लगभग 60 प्रतिशत समुद्री व्यापार का आवागमन होता है।

इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव ने अनेक देशों की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया है। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक नीति, बेल्ट एंड रोड पहल, सैन्य अड्डों का विस्तार तथा समुद्री शक्ति में वृद्धि ने क्षेत्रीय संतुलन को चुनौती दी है। इसके प्रतिरोध में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर Quad को सक्रिय बनाया। Quad का उद्देश्य किसी सैन्य गठबंधन का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मुक्त एवं नियम–आधारित समुद्री व्यवस्था को बनाए रखना है।

भारत के लिए इंडो–पैसिफिक क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी लगभग 90 प्रतिशत व्यापारिक गतिविधियाँ समुद्री मार्गों से संचालित होती हैं। भारत की 'Act East Policy' 'SAGAR' (Security and Growth for All in the Region) तथा इंडो–पैसिफिक महासागरीय पहल इस क्षेत्र में उसकी सक्रियता को दर्शाते हैं।

इंडो–पैसिफिक क्षेत्र क्या है?

इंडो. पैसिफिक का सीधा अर्थ है "हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मिलने का क्षेत्र"। यह वह विशाल भू.जलीय इलाका है जो भारत के पूर्वी तट से लेकर प्रशांत महासागर के द्वीपों तक फैला है, जिसमें दक्षिण–पूर्व एशिया, आस्ट्रेलिया, ओशिनिया और भारत के चारों ओर के सागरीय जल शामिल हैं। पहले लोग इन्हें अलग

–अलग "इंडियन ओशन" और "पैसिफिक ओशन" मानते थे, लेकिन 21वीं सदी के पहले दशकों में यह ज़रूरी लगने लगा कि दोनों को एक जुड़ी हुई रणनीतिक इकाई के रूप में देखा जाए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिन्जो आबे ने 2007 में भारत की संसद में दिए गए अपने भाषण "Confluence of the Two" में" में साफ–साफ कहा था कि प्रशांत और हिंद महासागर लगातार आपस में जुड़ रहे हैं और दोनों मिलकर एक "स्वतंत्रता और समृद्धि का सागर" बना रहे हैं। इसी भावना ने बाद में "फ्री एंड ओपन इंडो–पैसिफिक" (Free and Open Indo-Pacific) जैसे वाक्यांशों और चतुर्भुज (Quad) जैसे संरचनाओं के रूप में राजनीतिक रूप लिया। इंडो–पैसिफिक की अवधारणा कैसे बनी? इस शब्द की जड़ें 1920 के दशक में जर्मन राजनीतिक भूगोलवेत्ता कार्ल हौशोफर के लेखन में भी मिलती हैं, जिन्होंने भी भारी जनसंख्या और आर्थिक क्षमता वाले एशियाई ब्लॉक (जैसे जापान, चीन और भारत) को एक विशेष "इंडो–पैसिफिक" क्षेत्र के तौर पर देखा था। हालाँकि उनका विज़न और आज–कल की राजनयिक रोजिरोज़ी में बहुत फर्क है, पर यह खास बात है कि यह शब्द बीसवीं सदी में ही जन्मा, लेकिन बड़ा पैमाने पर शब्दकोश में तब आया जब 2007 में शिन्जो आबे ने भारत की संसद में इस अवधारणा को जीवंत और राजनीतिक रूप दिया। इस मॉडर्न संदर्भ में इंडो–पैसिफिक केवल भूगोल नहीं, बल्कि एक राजनयिक और रणनीतिक विचार है, जो चार बातों पर ज़ोर देता है– खुले समुद्री मार्ग, व्यापार की स्वतंत्रता, राज्यों की संप्रभुता और "अनिरंतर लेकिन नियमित" सुरक्षा संवाद।

इंडो–पैसिफिक का महत्व–

वैश्विक व्यापार का केंद्र इंडो–पैसिफिक का सबसे बड़ा वजन इस बात पर है कि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से होकर जाता है। अंदाज़न वैश्विक समुद्री व्यापार का 60% से अधिक इसी क्षेत्र के जलमार्गों से गुज़रता है, खासकर मलक्का मध्य, दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के चारों ओर के चॉकपॉइंट्स से। यही वह रास्ता है जिस पर मध्य–पूर्व से निकलने वाला कच्चा तेल, उर्वरक और अन्य बड़े उद्योग उत्पाद पूर्वी एशियाई देशों को पहुँचते हैं। इस इलाके में स्थित देश जैसे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण–पूर्व एशियाई राष्ट्र और दक्षिण कोरिया एक–दूसरे के लिए निर्यात, उपभोक्ता और निवेश बाज़ार हैं। इस वजह से इन देशों की आर्थिक ताकत और राजनीतिक आत्मनिर्भरता, दोनों ही इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा पर लगभग सीधे तौर पर निर्भर हैं। सामरिक प्रतिस्पर्धा का केंद्रइंडो–पैसिफिक को आज इतना अहम समझा जाता है क्योंकि यहाँ अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक खिंचाव सबसे साफ दिखता है। चीन ने अपने "बेल्ट एंड रोड" और दक्षिण चीन सागर में द्वीपों का दुरुपयोग जैसी नीतियों के जरिए इस क्षेत्र में अपनी सैन्य–आर्थिक उपस्थिति मज़बूत की है, जिसे दक्षिण.पूर्व एशियाई देश और अमेरिका जैसे राष्ट्र संप्रभुता और खुले मार्गों की धमकी के रूप में देखते हैं। इसी वजह से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और कई यूरोपीय देशों ने "फ्री एंड ओपन इंडो. पैसिफिक" जैसे वाक्यांशों के जरिए यह घोषित किया कि वे इस क्षेत्र में ऐसी प्रणाली चाहते हैं जहाँ कोई एक देश बलजबर्दस्ती नियंत्रण नहीं कर सके और सभी राज्य समान अधिकारों के साथ तरक्की कर सकें। जैसे–जैसे अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा है, वैसे.वैसे इंडो–पैसिफिक रणनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण बन गया है। ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक निर्भरताइंडो–पैसिफिक न केवल व्यापार का केंद्र है, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा भी है। लगभग दुनिया के तेल आपूर्ति का सैकड़ों करोड़ बैरल इसी क्षेत्र से होकर आता–जाता है, खासकर मलक्का जलडमरूमध्य के रास्ते। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और कई पूर्वी एशियाई देश साल का बड़ा हिस्सा ऊर्जा आयात के जरिए पूरा करते हैं, जो मुख्यतः मध्य.पूर्व और अफ्रीका से इसी मार्ग पर तैरते टैंकरों से आते हैं।इसीलिए इन देशों के लिए यह बहुत बड़ा जोखिम है कि अगर मलक्का, दक्षिण चीन सागर या हिंद महासागर के जलमार्गों में अचानक विवाद, युद्ध या रोक–टोक आ जाए, तो ऊर्जा आपूर्ति में बड़ा अंतर आ सकता है और इसका सीधा असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी भावना ने उन देशों को इंडो–पैसिफिक में नौसेना उपस्थिति, जल–सुरक्षा अभ्यास और द्विपक्षीय–बहुपक्षीय सुरक्षा संवाद बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। समुद्री सुरक्षा और नई चुनौतियाँ इंडो–पैसिफिक को इतना अहम बनाने में समुद्री सुरक्षा की चुनौतियाँ भी अहम भूमिका निभाती हैं। यहाँ समुद्री डकैती, अवैध फिशिंग, मानव तस्करी, खनिजों की अवैध खुदाई और आतंकवाद से जुड़े नौसैनिक गतिविधियों का खतरा लगातार बना रहता है। खासकर मलक्का जलडम–मध्य, सोमालिया के पार अफ्रीकी तट और दक्षिण.पूर्व एशियाई समुद्रों में इन तरह की घटनाएँ व्यापारिक जहाजों को लगातार जोखिम में डालती रही हैं। इसी वजह से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई छोटे राज्य समुद्री निगरानी, नौसेना जोड़.तोड़ (coordinated patrols), जानकारी–साझाकरण और क्षेत्रीय समझौतों के जरिए इस इलाके की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन देशों का तर्क है कि अगर समुद्री सुरक्षा बिगड़ी, तो न केवल व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होगी, बल्कि क्षेत्र की शांति और राजनीतिक स्थिरता भी दाव पर लग सकती है। भारत के लिए इंडो–पैसिफिक का विशेष महत्वभारत की दृष्टि में इंडो–पैसिफिक अपनी तटीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति,

प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और राजनीतिक प्रभाव के लिए बहुत ज़रूरी है।घ्घ इसी धारणा के आधार पर भारत ने "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" को और भी साफ और निर्णायक रूप दिया है, ताकि भारत यहाँ सिर्फ एक व्यापारिक देश नहीं, बल्कि एक सुरक्षा और नीति.निर्माता देश के रूप में उभर सके। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चतुर्भुज संवाद (Quad) जैसे रूप भी इसी सोच का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य खुले, कानून आधारित और नियम परक इंडो. पैसिफिक को बनाए रखना है। इस प्रकार इंडो–पैसिफिक केवल एक भू–राजनीतिक शब्द नहीं रहा, बल्कि आज भारत और कई देशों की लंबी–अवधि की विदेश नीति और रणनीति का हृदय बन चुका है।

इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका

इंडो–पैसिफिक क्षेत्र 21वीं शताब्दी की वैश्विक भू–राजनीति और आर्थिक गतिशीलता का केन्द्र बन चुका है। इस व्यापक क्षेत्र में भारत की भौगोलिक स्थिति–हिंद महासागर के हृदयस्थल में स्थित–उसे समुद्री मार्गों, ऊर्जा प्रवाह और व्यापारिक कनेक्टिविटी के संदर्भ में एक स्वाभाविक और निर्णायक भूमिका प्रदान करती है। वैश्विक शक्ति–संतुलन, समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में भारत की रणनीतिक प्राथमिकताएँ और नीतिगत पहलें इंडो–पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

1. Act East Policy

भारत की पारंपरिक "स्ववा मेंज" नीति का आरम्भ 1990 के दशक में आर्थिक और राजनीतिक जुड़ाव की आवश्यकता के आधार पर हुआ। 2014 के बाद इस नीतिगत धारणा को अधिक सक्रिय और क्रियान्वयन–उन्मुख स्वरूप देते हुए "Act East Policy" के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया। इस परिवर्तन का अर्थ केवल नाम परिवर्तन नहीं था, बल्कि दक्षिण–पूर्व एशिया तथा पूर्वी एशिया के साथ व्यवहारिक सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय नेतृत्व में भारत की भूमिका को ठोस रूप देना था। उद्देश्य और प्राथमिकताएँ आर्थिक समेकन व्यापार, निवेश और अवसंरचना कनेक्टिविटी के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक इंटिग्रेशन को बढ़ावा देना। सुरक्षा साझेदारी समुद्री और सीमा–आधारित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु रक्षा सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करना। बहुपक्षीय जुड़ावः ASEAN और उससे जुड़े मंचों में सक्रिय भागीदारी द्वारा क्षेत्रीय नीतियों और मानकों के निर्माण में योगदान देना कूटनीति टेक्निकल सहायता, परियोजना–समर्थन और लोगों–से–लोगों के कार्यक्रमों के माध्यम से भरोसा निर्मित करना। प्रमुख पहलें और कार्रवाईयां व्यापार–आधारित कदम भारत–ASEAN मुक्त व्यापार समझौतों का सुदृढ़ीकरण, तुल्यकालिक निवेश प्रवाह को आकर्षित करने के लिए व्यापार नीतियों का समन्वय। अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, जैसे सड़कों, रेलवे और बंदरगाह कनेक्शन में सहयोग, ताकि माल और लोगों की आवाजाही सुगम हो। रक्षा और समुद्री सहयोगरू संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, इंटर ऑपरेबिलिटी कार्यक्रम और हवाई सुरक्षा सहयोग, विशेषकर समुद्री सुरक्षा व समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिये। संस्कृति और लोगों का संपर्क शैक्षिक विनिमय, तकनीकी प्रशिक्षण और वीज़ा नीति में सहजता से दीर्घकालिक रिश्ते मज़बूत करना।

प्रभाव और सीमाएँ

Act East नीति ने भारत के रणनीतिक परिवेश में सकारात्मक बदलाव लाया—ASEAN के साथ भरोसा बढ़ा, व्यापारिक मार्ग खुले और क्षेत्रीय मंचों में भारत की आवाज़ प्रभावी रही। परन्तु चुनौतियाँ भी बनीं– अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की कठिनाइयाँ, सीमित तात्कालिक दिखने वाली भौतिक उपस्थिति और क्षेत्रीय देशों के साथ प्रतिस्पर्धी ऑफ़र (खासकर चीन की आर्थिक पहल) ने भारत की पहल की गति सीमित की।

2. SAGAR नीति

SAGAR (Security and Growth for All in the Region) भारत की समुद्री नीति का समेकित दृष्टिकोण है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह नीति उस मान्यता पर टिकी है कि हिंद महासागर क्षेत्र की शांति और समृद्धि केवल एक देश के प्रयासों से नहीं बल्कि सहयोगी और समावेशी भागीदारी से संभव है।मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत समुद्री सुरक्षा खुले और नियम–आधारित समुद्री ढाँचे का संरक्षण, समुद्री डकैती, आतंकवाद और अन्य गैर–पारंपरिक खतरों से निपटने के उपाय। क्षेत्रीय सहयोग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग से भरोसा निर्माण और साझा सुरक्षा ढाँचे का निर्माण। आपदा–प्रबंधन और HADR क्षेत्रीय आपदाओं के समय त्वरित मानवीय सहायता, बचाव और पुनर्निर्माण समर्थन। आर्थिक समावेशनः समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, मत्स्य उद्योग की सुरक्षा तथा समुद्री व्यापार के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को बढ़ाना। प्रमुख उपकरण और कार्यक्रम क्षमता निर्माण तटीय और द्वीप राष्ट्रों को तट रक्षक प्रशिक्षण, जहाज–उपकरण और समुद्री

निगरानी तकनीक प्रदान करना। समुद्री कूटनीतिरू द्विपक्षीय समझौतों और बहुपक्षीय मंचों पर नियम–आधारित आदेशों के समर्थन हेतु कूटनीतिक पहल। आपदा प्रतिक्रिया नेटवर्क क्षेत्रीय देशों के साथ संयुक्त अभ्यास और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना। सतत समुद्री प्रबंधन समुद्री क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, जैव–विविधता संरक्षित क्षेत्र और जिम्मेदार मछली पकड़ने के उपायों को बढ़ावा देना। राजनीतिक और सामरिक महत्त्व SAGAR नीति ने भारत को क्षेत्रीय नेतृत्व और सहायक साझेदार के रूप में स्थापित किया। नीति छोटे द्वीप देशों और तटीय समुदायों के साथ प्रायोगिक सहयोग के जरिए भारत की साख बढ़ाती है। फिर भी लागू करने में चुनौतियाँ विशेषकर संसाधन सीमाएँ, दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धताएं और क्षेत्र में वैकल्पिक शक्तियों की उपस्थिति नज़र आती हैं।

3.समुद्री शक्ति का विस्तार

इंडो–पैसिफिक में प्रभावी रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखने के लिए समुद्री शक्ति का विस्तार न केवल इच्छित है, बल्कि आवश्यक भी है। भारत की समुद्री शक्ति का विकास हिंद महासागर में लॉजिस्टिक रेंज, जहाज–उपस्थिति और निगरानी क्षमताओं के सामंजस्य से जुड़ा है। महत्त्वपूर्ण पहलें और आकाँक्षाएँ अंडमान–निकोबार कमान का सशक्तिकरण अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह को सामरिक रूप से सुधारा जा रहा है ताकि पूर्वी समुद्री गलियारों में भारत की चेतावनी, अनुशासन और त्वरित प्रत्युत्तर क्षमता बेहतर हो। यह स्थान हिंद–प्रशांत के पूर्वी प्रवेश मार्गों पर नजर रखने के लिये निर्णायक है। समुद्री निगरानी और डोमेन जागरूकता सैटेलाइट–आधारित ट्रैकिंग, समुद्री डोमेन जागरूकता नेटवर्क, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) और मल्टी–एजेंसी डेटा शेयरिंग से तटीय निगरानी को मजबूत किया जा रहा है। नौसैनिक आधुनिकीकरण बहुउद्देश्यीय पनडुब्बियाँ, विमानवाहक पोत, मिसाइल–नौकाएँ तथा तट–रक्षक क्षमताओं का उन्नयन ये कदम समुद्री ताकत की पहुँच और संचालनात्मक प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। बहुपक्षीय अभ्यास और साझेदारी मालाबार, समुंद्र–आभ्यास और द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों के माध्यम से सामूहिक प्रतिक्रिया, मानक संयोजन और क्षमता साझा की जा रही है।

प्रभाव और प्रतिकूलताएँ

समुद्री शक्ति विस्तार से भारत को समुद्री मार्गों की सुरक्षा, मानवीय सहायता प्रदायगी और रणनीतिक निराकरण में अधिक प्रभावक्षमता मिली है। तथापि इससे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा तेज हुई है; विशेषकर चीन की नौसैनिक विस्तार नीतियों के मद्देनजर रोष और तनाव के मौके बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उच्च तकनीकी निवेश और निरन्तर परिचालन–लागत के कारण संसाधनों का दीर्घकालिक प्रबंध चुनौतीपूर्ण बना रहता है।

4. इंडो–पैसिफिक महासागरीय पहल (IPOI)

2019 में घोषित IPOI भारत का एक व्यापक समर्पित समुद्री पहल है, जिसका उद्देश्य इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में सहयोगी सुरक्षा, संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। IPOI भारत की कूटनीतिक व नीति पहल का एक सुसंगठित रूप है, जो क्षेत्रीय रचनात्मकता और साझा जिम्मेदारी पर बल देता है।मुख्य घटक और क्रियान्वयन रणनीतियाँसमुद्री सुरक्षा फ्रेमवर्क समुद्री डकैती, तस्करी और गैरकानूनी मछली पकड़ने जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु नियम–आधारित सहयोग बढ़ाना। संसाधन प्रबंधन और वैज्ञानिक सहयोगरू समुद्री पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण हेतु क्षेत्रीय अनुसंधान, डेटा साझाकरण और नीति समन्वयन को प्रोत्साहित करना। क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता छोटे द्वीप राष्ट्रों एवं तटीय समुदायों को मानव संसाधन विकास, निगरानी उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करना। आपदा–प्रतिक्रिया और HADR नेटवर्क आपदा के समय साझा त्वरित प्रतिसाद तंत्र और आपातकालीन संसाधन साझा करने के लिए मंच विकसित करना।

परिणाम, अवसर और चुनौतियाँ

IPOI ने क्षेत्रीय देशों के बीच भरोसा निर्माण और कार्यान्वयन आधारित सहयोग को बढ़ावा दिया है। यह पहल भारत की विचारधारा नियम–आधारित मुक्त समुद्र, क्षेत्रीय समावेशिता और साझा विकास का द्योतक है। चुनौतियाँ प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संसाधन समर्पण, कई देशों के साथ समन्वय जटिलता और प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं के बीच प्राथमिकताओं का टकराव।

Quad और भारत

Quad भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक समूह है।

Quad की शुरुआत 2007 में हुई, लेकिन चीन के विरोध और राजनीतिक कारणों से यह निष्क्रिय हो गया। 2017 के बाद चीन की आक्रामक नीतियों के कारण इसे पुनर्जीवित किया गया।

Quad के उद्देश्य

1. मुक्त और खुला इंडो–पैसिफिक

इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था बनाए रखना क्वाड का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी देश को नौवहन या व्यापार के लिए बाधित नहीं किया जाना चाहिए और समुद्र में गतिविधियाँ खुले, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप हों। क्वाड के साथी देश मिलकर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्षेत्र में शांति बनी रहे और व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रहें, ताकि आर्थिक क्रियाएँ और समुद्री यातायात निर्बाध रूप से चल सकें।

2.चीन के प्रभाव को संतुलित करना

हालाँकि क्वाड को औपचारिक रूप से चीन के खिलाफ गठबंधन नहीं कहा जाता, फिर भी इसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते चीन के प्रभाव को एक तरह से संतुलित करना है। सदस्य देश मिलकर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्रीय शक्ति द्वारा सीमा–वीसाम्य या विस्तारवादी कदमों से पड़ोसी देशों की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित न हो। इस संतुलन–रखने की कोशिश में कूटनीतिक दबाव, सुरक्षा साझेदारी और आर्थिक विकल्पों का समावेश होता है।

3.समुद्री सहयोग

क्वाड देशों के बीच समुद्री सहयोग का दायरा काफी व्यापक है– इसमें साझा नौसैनिक अभ्यास, समुद्री निगरानी और संकट के समय आपसी मदद शामिल है। नियमित संयुक्त अभ्यासों से तैनाती और आपसी तालमेल में सुधार आता है, जबकि समुद्री निगरानी से समुद्री सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। यह सहयोग छोटे देशों को भी समुद्री सुरक्षा के मामलों में समर्थन देने में मदद करता है।

4. तकनीकी और आर्थिक सहयोग

क्वाड का एक और अहम पहलू तकनीक और अर्थव्यवस्था में साझेदारी है। सदस्य देश 5G जैसी उभरती तकनीकों, साइबर सुरक्षा उपायों और डिजिटल अवसंरचना पर काम साझा करते हैं। इसके अलावा क्वाड आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करने, निवेश सहयोग और विकास परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के प्रयास कर रहा है।

5. स्वास्थ्य और सार्वजनिक–हित के सहयोग

क्वाड देशों के बीच स्वास्थ्य से जुड़ी साझेदारियाँ भी बढ़ रही हैं, जिसमें वैक्सीन निर्माण व वितरण, आपातकालीन स्वास्थ्य आपूर्ति और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती शामिल है। ऐसे सहयोग से महामारी या अन्य स्वास्थ्य संकटों के समय तेजी से और प्रभावी मदद पहुंचाने में आसानी होती है, साथ ही पेटेंट और उत्पादन क्षमता को साझा कर के स्थानीय क्षमताओं को भी बढ़ाया जा सकता है।

चीन एक चुनौती

भारत के लिए चीन केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सामरिक चुनौती भी है।

1.दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रुख

चीन ने दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा बहुत व्यापक तौर पर रखा है और वह वहां पर कृत्रिम द्वीपों और सैन्य सुविधाओं का निर्माण कर रहा है। इन द्वीपों पर रनवे, रडार और मिसाइल तैनात करने जैसे कदमों ने इलाके की सामरिक संवेदनशीलता बढ़ा दी है। आसपास की कई देशों– जैसे फिलिपींस, वियतनाम, मलेशिया के साथ समुद्री सीमाओं और जल मार्गों पर टकराव के मौके बढ़ गए हैं, जिससे समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों पर असर पड़ता है। भारत इस क्षेत्र को खुले समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से अहम मानता है, इसलिए चीन की इस गतिविधि को केवल क्षेत्रीय रियल एस्टेट से बढ़कर एक सुरक्षा चुनौती के रूप में देखता है।

2. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के जरिए बढ़ता प्रभाव

चीन का Belt and Road Initiative एक व्यापक निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ना है। वाहन, बंदरगाह, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से चीन कई देशों में आर्थिक जुड़ाव बढ़ा रहा है। भारत ने BRI के कुछ भागों, खासकर CPEC (China–Pakistan Economic Corridor) का विरोध इसलिए किया क्योंकि वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है; New Delhi का तर्क है कि यह क्षेत्र विवादित है और इस तरह के प्रोजेक्टों को वैध ठहराना अंतरराष्ट्रीय क़ानून के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, BRI के जरिए चीन का दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ता दिखता है, जिससे क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता प्रभावित होती है– यह भारत की भू–राजनीतिक चिंताओं का

एक बड़ा कारण है।

3. String of purls"पर्ल्स की माला' यानी समुद्री आधारभूत संरचनाओं का जाल

चीन धीरे–धीरे हिंद महासागर के मार्गो पर पोर्ट और सुविधाएं विकसित कर रहा है जिसे अनेक विशेषज्ञ "String of Pearls" रणनीति कहते हैं। इसमें ग्वादर (पाकिस्तान), हंबनटोटा (श्रीलंका) और जिबूती जैसे स्थान शामिल हैं, जहाँ चीन के निवेश, लीज़ समझौते और कभी–कभी सैन्य सहयोग से उसे क्षेत्र में पहुँच और प्रभाव मिला है। ऐसे नौसैनिक–लॉजिस्टिक और बंदरगाह नेटवर्क से समुद्री मार्गों पर निगरानी और जरूरत पड़ने पर त्वरित तैकियों की तैनाती की सम्भावना बढ़ती है। भारत के लिए हिंद महासागर पारंपरिक तौर पर एक रणनीतिक क्षेत्र रहा है; इसलिए इन विकासों को वह अपनी समुद्री सुरक्षा और लॉजिस्टिक नियंत्रितता के लिए प्रतिद्वंद्विता समझता है।

4.सीमाई विवाद और तनाव, खासकर Galwan का टकराव

भारत और चीन के बीच लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसी सीमाई रेखाओं पर दशकों से असहमति रही है। हाल के वर्षों में इस विवाद ने गंभीर रूप लिया, जिसका एक प्रमुख उदाहरण Galwan घाटी में 2020 का हिंसक सामना है। उस झड़प में दोनों पक्षों को मानवीय और सैन्य नुकसान हुआ और इसके बाद सीमा पर दोनों देशों ने सैनिकों की तैनाती और कड़े सुरक्षा प्रबंध बढ़ा दिए। इस तरह की घटनाएँ द्विपक्षीय विश्वास पर भारी असर डालती हैं और सैन्य तथा कूटनीतिक स्तर पर रिश्तों में लंबा ठंडापन ला देती हैं। भारत इस तरह के सीमाई कदमों को न केवल क्षेत्रीय सीमा–प्रबंधन का मामला मानता है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा प्राथमिक प्रश्न भी समझता है।

भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया

1. सामरिक साझेदारी

भारत ने अपनी सुरक्षा चुनौतियों का सामना अकेले करने के बजाय भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर करने का रास्ता चुना है। इसी सोच के तहत वह अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रक्षा–क्षेत्र में संबंध गहरे कर रहा है। इन सहयोगों का स्वरूप मात्र हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं है; संयुक्त अभ्यासों, खुफिया साझाकरण, समुद्री सुरक्षा सहयोग और लॉजिस्टिक्स सुविधा जैसे पहल भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर समुद्री अभ्यास और पोत–रखरखाव समझौते यह सुनिश्चित करते हैं कि क्षेत्रीय अवरोधों के समय भारतीय नौसेना को सहयोग मिल सके। इस बहुपक्षीय और द्विपक्षीय साझेदारी के जरिए भारत अपनी रणनीतिक मजबूती बढ़ाते हुए समकक्ष देशों के साथ भरोसे का वातावरण बना रहा है।

2. सैन्य आधुनिकीकरण

रक्षा बलों की तैयारी आधुनिक खतरे के अनुरूप हो, इस लक्ष्य से भारत लगातार अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण कर रहा है। नौसेना और वायुसेना दोनों में नई पारंपरिक क्षमताओं के साथ–साथ आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी प्रणाली और सटीक हथियारों का समावेश हो रहा है। उदाहरण के लिए, अग्रिम पीढ़ी के विमान, स्पर्शोन्मुख रडार, समुद्री गश्ती टैक्नोलॉजी और स्वदेशी युद्धपोतों के विकास पर निरंतर निवेश जारी है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल उपकरण बढ़ाना नहीं, बल्कि त्वरित तैनाती, लंबी अवधि की परिचालन क्षमता और समग्र सशस्त्र बलों की प्रत्युत्तर क्षमता को मजबूत करना भी है।

3. कनेक्टिविटी परियोजनाएँ

रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए केवल सैन्य या राजनीतिक उपाय ही पर्याप्त नहीं; बेहतर कनेक्टिविटी भी आवश्यक है। इसी भाव से भारत ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ध्यान दिया हैकृजैसे चाबहार बंदरगाह, इंस्टनैशनल (INSTC) और मध्य एशिया के साथ सड़क–रेल संपर्कों को सुदृढ़ करना। चाबहार के जरिए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का वैकल्पिक मार्ग मिलता है, जबकि INSTC (इंटरनैशनल नॉर्थ–साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर) व्यापार मार्गों को छोटा कर रणनीतिक वैकल्प्य मार्ग उपलब्ध कराता है। इन पहलों से न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा, बल्कि क्षेत्र में भारत की सामरिक पहुँच और सामरिक संबंधों की स्थिरता भी मजबूत होगी।

4. आर्थिक आत्मनिर्भरता

रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आर्थिक आधार मजबूत होना ज़रूरी है। "आत्मनिर्भर भारत" का लक्ष्य इसी दिशा में है– मूल्यवान क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविध बनाकर एक–देश पर निर्भरता घटाना। इसके तहत उच्च–प्राथमिकता वाले उद्योगों में निवेश, स्वदेशी निर्माताओं का

समर्थन और वैकल्पिक सप्लायर खोजने की नीति अपनाई जा रही है। इससे संकट के समय आपूर्ति में व्यवधान कम होंगे और नीति–निर्माता विदेश नीति में अधिक लचीलापन हासिल कर सकेंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता का मकसद केवल संरक्षण नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ उत्पादन क्षमताओं का विकास भी है।

निष्कर्ष

इंडो– पैसिफिक क्षेत्र आज वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का केन्द्र बन चुका है। इस भू–राजनीतिक परिवर्तन के पीछे चीन की निरंतर आर्थिक वृद्धि, उसके नौसैनिक विस्तार और क्षेत्रीय अवसंरचनात्मक परियोजनाएँ जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) मुख्य कारण हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों, सैटलाइट से मिली उपग्रह तस्वीरों और कृत्रिम द्वीप निर्माण की घटनाओं ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ाया है, जिससे पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्तियों का रुझान इस क्षेत्र की सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी की ओर बढ़ा है। इस संदर्भ में QUAD (भारत–अमेरिका–जापान–ऑस्ट्रेलिया) का दोहराव और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, जैसे मालाबार वर्कआउट्स, इंडो– पैसिफिक में सामरिक सामंजस्य का एक स्पष्ट संकेत हैं। भारत ने पिछले दशक में अपनी इंडो– पैसिफिक नीति को व्यवस्थित तरीके से आकार दिया है। 2018 और 2019 में प्रकाशित सरकारी नीतिगत दस्तावेज़ों ने भारत की प्राथमिकताओं खुले और नियम–आधारित समुद्री क्रम, आर्थिक कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षाकृको रेखांकित किया। व्यवहार में भारत ने नौसेना क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर निवेश किया हैरू नए विमानवाहक पोत INS विक्रांत का परिचालन, आधुनिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण और विदेशी अड्डों व लॉजिस्टिक्स समझौतों पर ध्यान (जैसे फ्रांस, यूके, सिंगापुर के साथ।) वायुशक्ति में आधुनिक लड़ाकू विमानों और निगरानी क्षमताओं के विस्तार ने भी भारत के प्रत्युत्तर क्षमताओं को मजबूत किया है। आर्थिक माने तो भारत ने आपूर्ति–श्रृंखला विविधीकरण और "आत्मनिर्भर" पहल के माध्यम से चीन–निर्भरता घटाने की कवायद तेज की है। चिप्स, दवा निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रतिबंधित आयात पर नीतिगत प्रोत्साहन और उत्पादन–लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) योजनाएं लागू की गई हैं। इसी तरह, कनेक्टिविटी में भारत–इरान के चाबहार बंदरगाह पर निवेश और इंटरनैशनल नॉर्थ–साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) में भागीदारी ने व्यापार के वैकल्पिक मार्ग स्थापित किए हैं जो ईरान, कजाखस्तान और रूस तक पहुंच को आसान बनाते हैं। मध्य एशिया और बंगाल की खाड़ी के साथ द्विपक्षीय परियोजनाएँ भी बढ़ रहीं हैं, जिससे रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव दोनों मजबूत होते हैं।कूटनीति में, भारत ने बहुपक्षीय मंचों और द्विपक्षीय वार्ताओं दोनों में सक्रियता दिखाई है—ASEAN, East Asia Summit और G20 में उसकी आवाज़ अधिक प्रभावी हुई है। साथ ही, रक्षा साझेदारियों में संयुक्त प्रशिक्षण, खुफिया आदान–प्रदान और लॉजिस्टिक समझौते (जैसे बेसिक स्टोर और इमार्जेंसी रिफ्यूलिंग) भारत की परिचालन क्षमता बढ़ा रहे हैं। मानवीय और विकास सहयोग व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता, समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण और साइबर–क्षमता निर्माण ने भी क्षेत्रीय देशों के साथ भरोसा बनाया है। भविष्य में, वैश्विक शक्ति–संतुलन एशिया की ओर झुकता दिख रहा है; ऐसे में भारत की भूमिका और भी निर्णायक होगी। यदि भारत अपनी आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखे, उच्च–तकनीकी उत्पादन में निवेश बढ़ाए, और रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता तथा बहुपक्षीय साझेदारी को संतुलित करे, तो वह इंडो– पैसिफिक में स्थिरता और सामरिक संतुलन का एक प्रमुख स्तंभ बन सकता है। इससे न केवल समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार और छोटे देशों की रणनीतिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होगी।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ सूची–

1. अबे, शिंजो. (2007). कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज (दो समुद्रों का संगम). भारतीय संसद में दिया गया ऐतिहासिक भाषण, नई दिल्ली।
2. कपलॉ, रॉबर्ट डी. (2010). मानसून द इंडियन ओशन एंड द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर (मानसून हिंद महासागर और अमेरिकी शक्ति का भविष्य). रैंडम हाउस।

3. कोंडापल्ली, श्रीकांत. (2020). चाइनाज नेवल पावर एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडो–पैसिफिक (चीन की नौसैनिक शक्ति और इंडो–पैसिफिक के लिए इसके निहितार्थ). जेएनयू रिसर्च पेपर्स।
4. कौसिकन, बिलीहारी. (2018). डीलिंग विद चाइना एन आसियान पर्सपेक्टिव ऑन द इंडो–पैसिफिक (चीन से निपटनारू इंडो–पैसिफिक पर आसियान का दृष्टिकोण). सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. क्रोनिन, पैट्रिक एम. (2021). द नेक्स्ट वैली टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी इन द प्दकव–च्बपपिब (अगली घाटीरू इंडो–पैसिफिक में तकनीक और सुरक्षा). हडसन इंस्टीट्यूट।
6. खुराना, गुरप्रीत एस. (2007). सिक्योरिटी ऑफ सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द इंडियन ओशन (हिंद महासागर में समुद्री संचार लाइनों की सुरक्षा). स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, 31(1), 139–153।
7. ग्रीन, माइकल. (2017). बाय मोर दैन प्रोविडेंसरू ग्रैंड स्ट्रैटेजी एंड अमेरिकन पावर इन द एशिया पैसिफिक सिंस 1783 (ईश्वरीय कृपा से अधिकरू 1783 से एशिया प्रशांत में भव्य रणनीति और अमेरिकी शक्ति). कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. चेलानी, ब्रह्मा. (2011). वाटररू एशियाज न्यू बैटलग्राउंड (जलरू एशिया का नया युद्धक्षेत्र). जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. टेलीस, एशले जे. (2020). स्ट्रैटेजिक एशियारू एक्सपैंडिंग होराइजन्स इन द इंडो–पैसिफिक (रणनीतिक एशियारू हिंद–प्रशांत में क्षितिज का विस्तार). नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च।
10. नागाओ, सटोरू. (2019). द स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया–जापान–यूएस कोऑपरेशन इन द इंडो–पैसिफिक (हिंद–प्रशांत में भारत–जापान–अमेरिका सहयोग का रणनीतिक महत्व). हडसन रिपोर्ट।
11. पंत, हर्ष वी. (2021). इंडिया एंड द क्वाडरू स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज एंड चौलेंजेस इन द इंडो–पैसिफिक (भारत और क्वाडरू हिंद–प्रशांत में रणनीतिक अवसर और चुनौतियां). ओरिएंट ब्लैकस्वान।
12. बरुआ, दारशना एम. (2022). द स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ आइलैंड्स इन द इंडो–पैसिफिक (इंडो–पैसिफिक में द्वीपों का रणनीतिक महत्व). कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस।
13. ब्रूस्टर, डेविड. (2014). इंडियाज ओशनरू द स्टोरी ऑफ इंडियाज बिड फॉर रीजनल लीडरशिप (भारत का महासागररू क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए भारत के प्रयास की कहानी). रूटलेज।
14. महानकेन, थॉमस जी. (2018). स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन इन द इंडो–पैसिफिक (इंडो–पैसिफिक में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा). सीएसबीए (CSBA) पब्लिकेशन्स।
15. मेडकाफ, रोरी. (2020), कॉन्टेस्टिंग द इंडो–पैसिफिकरू व्हाई चाइना वोन्ट मैप द फ्यूचर (इंडो–पैसिफिक का मुकाबलारू चीन भविष्य का नक्शा क्यों नहीं तय करेगा), ला ट्रोब यूनिवर्सिटी प्रेस।
16. मोहन, सी. राजा. (2012). समुद्र मंथन, सिनो–इंडियन राइवलरी इन द इंडो–पैसिफिक (समुद्र मंथन, हिंद–प्रशांत में भारत–चीन प्रतिद्वंद्विता). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
17. राजगोपालन, राजेश्वरी पिल्लई. (2021), द इंडो–पैसिफिक थियेटररू स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन (इंडो–पैसिफिक थिएटर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और सहयोग). ओआरएफ रिसर्च सीरीज।
18. राटनर, एली. (2019). राइजिंग टू द चाइना चौलेंजरू रिन्यूइंग अमेरिकन कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडो–पैसिफिक (चीन की चुनौती का सामना, इंडो–पैसिफिक में अमेरिकी प्रतिस्पर्धात्मकता का नवीनीकरण), सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी।
19. फेगेनबाम, ईवान ए. (2020). द इंडो–पैसिफिकरू फ्रेमिंग द रीजन्स इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी फ्यूचर (इंडो–पैसिफिकरू क्षेत्र के आर्थिक और सुरक्षा भविष्य का निर्धारण), कार्नेगी पेपर्स।
20. हक्सले, टिम और जोन्स, वॉन जी, (2023). एशिया–पैसिफिक रीजनल सिक्योरिटी असेसमेंट (एशिया–प्रशांत क्षेत्रीय सुरक्षा मूल्यांकन). इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (IISS)।
21. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, (2019, नवंबर 4). इंडो–पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) (हिंद–प्रशांत महासागर पहल), आधिकारिक नीति दस्तावेज और मीडिया ब्रीफिंग, नई दिल्ली।
22. विदेश मंत्रालय (इंडो–पैसिफिक डिवीजन), भारत सरकार. (2021). इंडियाज विजन फॉर द इंडो–पैसिफिक, फ्री, ओपन एंड इन्क्लूसिव (हिंद–प्रशांत के लिए भारत का दृष्टिकोण, स्वतंत्र, खुला और समावेशी), आधिकारिक नीति संक्षिप्तिका (Policy Brief), नई दिल्ली।

Cite this Article-

'विजय कुमार यादव', "इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिकाः QUAD और चीन एक चुनौती", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:3, Issue:02, February 2026.

"Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY), allowing others to use, share, modify, and distribute it with proper credit to the author."